

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 19

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 28 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय ने किसान परिषद की पहली बैठक आयोजित की

दुबई, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय ने किसान परिषद की पहली बैठक की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री मरियम बिनत मोहम्मद अल्महेरी ने की। बैठक में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और वाणिज्यिक मूल्य बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूएई में स्थायी आधुनिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निर्देशों पर प्रकाश डाला गया। मंत्री ने कहा, खाद्य सुरक्षा यूएई की एक रणनीतिक प्राथमिकता है, जिसे हम देश में संबंधित हितधारकों के सहयोग से अपने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और उन्नत कृषि प्रथाओं को मुख्यधारा में लाने के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, किसान परिषद की स्थापना इस प्राथमिकता को आगे बढ़ाएगी। यह क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों और उन पर काबू पाने के सर्वोत्तम तरीकों को उजागर करेगी। अपनी सदस्यता के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए परिषद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की आवाज सुनी जाए और प्रासंगिक सरकारी योजनाओं व कृषक समुदाय के बीच उन्हें सहयोग देने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। उन्होंने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुपालन व पर्यावरण और जलवायु पर क्षेत्र के प्रभावों को कम करने वाले आधुनिक कृषि में उनके बदलाव के माध्यम से क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्थानीय किसानों की प्रशंसा की। बैठक के एजेंडे में परिषद के शासनादेशों का अवलोकन किया गया। इनमें अत्याधुनिक खेती पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने, एक वार्षिक कृषि योजना विकसित करने, लागू कृषि प्रणालियों की पहचान करने, चयनित खेतों पर क्रियान्वित किए जाने वाले अनुप्रयुक्त कृषि अनुसंधान कार्यक्रमों को अधिकृत करने, किसानों के लिए क्षमता निर्माण व अनुभव साझा करने की गतिविधियों का आयोजन करने और वार्षिक कृषि



उत्पादन कार्यक्रमों को मंजूरी देने व विपणन योजनाओं का उत्पादन करना शामिल है। सदस्यों ने प्राथमिकता वाली चुनौतियों और परियोजनाओं की पहचान करने, कार्य योजना विकसित करने और कार्य व समय-सीमा निर्धारित करने के लिए परिषद की कार्य प्रक्रियाओं को रेखांकित किया। उन्होंने 22 नवंबर, 2023 को यूएई की वार्षिक सरकार की बैठक में सरकारी संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा पर भी चर्चा की, जहां वे स्थानीय खेतों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर और 2030 तक खाद्य क्षेत्रों में निवेश को 100 फीसदी तक बढ़ाकर 2023 तक स्थानीय खेतों से अपनी खाद्य संबंधी खरीद का 50 फीसदी हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा परिषद ने एमिरेट्स डेवलपमेंट बैंक द्वारा आधुनिक कृषि एसएमई और स्टार्ट-अप को पेश किए गए वित्त समाधानों की खोज की और किसानों के लिए लक्षित विस्तार सेवाओं के विकास में अगले कदमों पर प्रकाश डाला। इस संदर्भ में MOCCAE अगले कुछ हफ्तों में किसानों के डेटाबेस को अपडेट करेगा। अजमान किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिषद के सदस्य हामिद ओबैद अल जाबी ने कृषि क्षेत्र के लिए सरकारी फैसलों और भविष्य की योजनाओं में किसानों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिषद के सदस्य हामिद अल हमद ने कहा, परिषद एक ऐसा मंच है, जो सरकार और निजी क्षेत्र के निर्णय निर्माताओं व विशेषज्ञों को संबंधित नीतियों और दिशाओं के साथ ही क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के लिए साथ लाता है।

केंद्र सरकार को झटका, एनजीटी ने निर्माण परियोजनाओं पर पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना पर रोक बढ़ाई

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्माण परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना पर रोक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन की शर्तों में संशोधन करते हुए 14 नवंबर, 2018 को नई अधिसूचना जारी की थी। जिसके मुताबिक, केंद्र सरकार ने 20,000 वर्ग मीटर से 50,000 वर्ग मीटर तक क्षेत्र पर भवन या निर्माण परियोजनाओं के संबंध में नगर पालिकाओं, विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों सहित स्थानीय निकायों को पर्यावरण से संबंधित परिस्थितियों का अनुपालन सुनिश्चित करने



की शक्ति प्रदान की थी।

इसके अलावा सरकार ने इन स्थानीय निकायों को 20,000 वर्ग मीटर से 1,50,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र वाले औद्योगिक शेड, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में भवन निर्माण की अनुमति और कब्जा प्रमाण

पत्र देने की शक्ति भी प्रदान की थी। सरकार के इस आदेश को एनजीटी में चुनौती दी गई थी। जिसमें कहा गया था कि संशोधित ईआईए सतत विकास और एहतियाती सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) को मूल्यांकन की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस एके गोयल की पीठ ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी करने के बाद ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2018 में अधिसूचना पर रोक लगा दी और आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, क्योंकि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।

जहरीले पारे के संपर्क में आने को रिकॉर्ड करते हैं मछलियों की आंखों के लेंस

नई दिल्ली। मछलियों की आंखों के लेंस जहरीले पारे के संपर्क में आने को रिकॉर्ड करते हैं - शोधफोटो साभार - विकिमीडिया कॉमन्स, आंद्रे करवाथ उर्फ आका, मछली की आंखों के लेंस में ओटोलिथ उम्र बढ़ने के साथ-साथ पारे की मात्रा भी बढ़ती है फोटो साभार - विकिमीडिया कॉमन्स, आंद्रे करवाथ उर्फ आका, मछली की आंखों के लेंस में ओटोलिथ उम्र बढ़ने के साथ-साथ पारे की मात्रा भी बढ़ती है दुनिया भर में पारे से होने वाला प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, खासकर अजन्मे शिशुओं और छोटे बच्चे इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। मिथाइलमर्करी से संपर्क तब होता है जब पारा झीलों और धाराओं में मिलता है। यह बच्चों के मस्तिष्क के विकास को नुकसान पहुंचा सकता है और वयस्कों में बोलने में दिक्कत और मांसपेशियों की कमजोरी सहित कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है।

यह उन लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है जो मुख्य भोजन स्रोत के रूप में समुद्री भोजन का सेवन करते हैं। मिथाइलमर्करी मछली और अन्य जीवों के स्वास्थ्य और प्रजनन के लिए भी खतरा पैदा करता है। मनुष्य, पशु और पक्षी जब मछली और शेलफिश खाते हैं तो वे मिथाइलमर्करी के संपर्क में आते हैं। वैज्ञानिक दशकों से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मछली कब और कैसे पारा जमा करती है। यह जानकारी विभिन्न जल निकायों और परिदृश्यों में पारे के खतरों का आकलन करने और पारे के उत्सर्जन को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए नीतिगत परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। दशकों से, वैज्ञानिकों ने मछलियों के विकास, प्रवासन, आहार और कुछ प्रदूषकों के संपर्क में आने के समय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए फिश ईयर स्टोन का इस्तेमाल किया है, जिन्हें ओटोलिथ के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की ये छोटी संरचनाएं, मोटे तौर पर मटर के आकार की, मछलियों के आंतरिक कानों के अंदर बनती हैं, जहां वे सुनने और संतुलन को नियमित करने में मदद करती हैं। ओटोलिथ इस बात का सुराग भी दे सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन मछली को कैसे प्रभावित कर रहा है। लेकिन पारा सहित कुछ प्रदूषकों को ओटोलिथ में शामिल नहीं



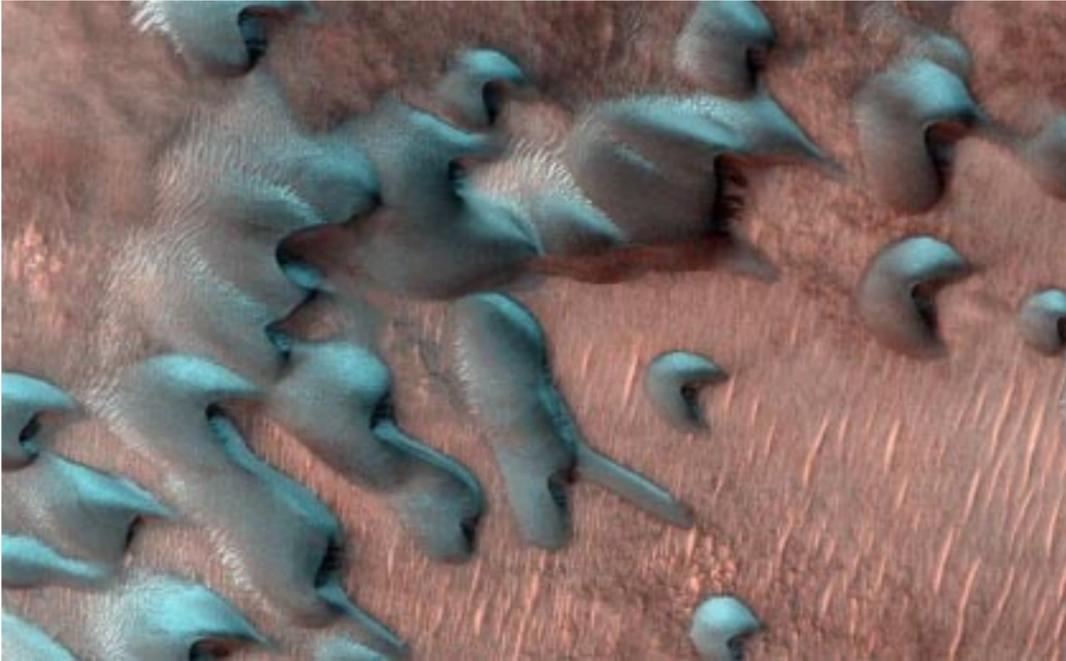
किया जाता है। बल्कि, वे उन ऊतकों से बहुत मजबूती से जुड़े हैं जिनमें सल्फर होता है, जैसे कि मांसपेशियों के ऊतक। इसीलिए पारा प्रदूषण के कारण संदूषण का आकलन करने के लिए मांसपेशियों के ऊतकों का ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। नए अध्ययन में, मछली की आंखों में पारे को माप कर हर मछली के जीवनकाल में इसके संपर्क में आने का वर्णन किया गया है। यह काम इस शक्तिशाली न्यूरो-टॉक्सिकेंट के लिए मछली के जीवनकाल के खतरों को समझने की नई संभावनाओं को सामने लाता है।

मछली के कान और आंखों में सुराग- आज, वैज्ञानिक मछली में पारे के अवशोषण का विश्लेषण यह माप कर करते हैं कि यह मछली के पूरे शरीर में कितना जमा होता है या अक्सर केवल फाइलों में यानी मांसपेशियों के ऊतकों में जमा होता है। यह तरीका हमें बताता है कि मछली ने अपने जीवनकाल में कितना पारा जमा किया है, लेकिन यह हमें विशेष रूप से यह नहीं बताता है कि मछली अपने जीवन में कब पारे के संपर्क में आई, यहां पर समयकाल गायब है। पारे की मात्रा किसी भी मछली प्रजाति के भीतर व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1991 से 2010 तक, अमेरिकी सरकार के मॉनिटर ने कॉड में पारे के स्तर का पता लगाया, जो औसतन 0.111 भाग प्रति मिलियन था, लेकिन 0.989 भाग प्रति मिलियन, नौ गुना अंतर था। इससे पता चलता है कि समय के साथ पारे के उत्सर्जन में बदलाव के अलावा, एक मछली की चाल और आहार को प्रभावित कर सकते हैं। शोधकर्ता ने कहा हमने अध्ययन में, एक नई विधि का उपयोग किया है जो मछली की आंखों के लेंस में ओटोलिथ उम्र बढ़ने और पारे की माप को जोड़ती है, ताकि मछली की आंख में पारे की सांद्रता की अवधि का पता लगाया जा सके। आंख के लेंस शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें सल्फर अधिक होता है जो सीधे पानी से या मछली के आहार से पारा अवशोषित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मिथाइलमर्करी कुछ अंगों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसमें आंख के लेंस भी शामिल हैं। यह मछली की दृष्टि को क्षीण कर सकता है। शोध ओटोलिथ का उपयोग करके एक मछली की उम्र बढ़ने की तकनीक से शुरू होता है। जैसे-जैसे मछली बढ़ती है, उसकी उम्र भी बढ़ती है, हर साल उसके ओटोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट की परतें जुड़ती हैं। हम सालभर में जुड़ी परतों के बीच की दूरी को मापकर मछली की उम्र और विकास दर का अनुमान लगा सकते हैं, जिसे एनुली कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वनवासी पेड़ों को उनके छेदों को मापकर उसकी आयु का पता लगाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि एक मछली की आंख उस दर से बढ़ती है जो उसके ओटोलिथ के विकास के समानुपाती होती है। तो हमारे विश्लेषण में, हम उस आनुपातिक दूरी को लागू करते हैं जो हमें मछली के ओटोलिथ में उसकी आंखों के लेंस पर मिली थी। हमारी नाभीय प्रजातियों के लिए, राउंड गोबी (नियोगोबियस मेलानोस्टोमस), मछली प्रजाति में इन दो मापों के बीच रैखिक संबंध मजबूत है। शोधकर्ता ने बताया कि जब आंख का लेंस बढ़ता है और पारा जमा करता है, तो हम ओटोलिथ के साथ सामंजस्य बैठा कर मछली

के संपर्क में आने का पता लगा सकते हैं। क्योंकि मछली की आंखों का लेंस जीवन भर परतों में बढ़ता है, हम आजीवन खतरे के कालक्रम को उजागर कर सकते हैं।

क्या जलवायु में बदलाव से जुड़ी कोई कड़ी है?- शोधकर्ता ने कहा इस नई पद्धति के साथ, हम एक मछली के जीवन काल में पारे के खतरे वाले कालक्रम का पता लगाना शुरू कर सकते हैं। हम इस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे जीवन इतिहास की घटनाएं, जैसे कि प्रवासन और आहार परिवर्तन या अस्थायी घटनाएं जैसे वर्ष के निश्चित समय में पानी में कम घुलित ऑक्सीजन का स्तर, मछली में पारे के स्तर को प्रभावित कर सकता है। इस पद्धति की ताकत यह है कि यह अलग-अलग मछलियों के लिए जानकारी प्रदान करती है, जो इंसानों की तरह ही मायने रखती है। अलग-अलग मछलियों में शिकार को पकड़ने और तनाव से बचने या सहन करने की अलग-अलग क्षमता होती है, जो सभी उनकी वृद्धि और पारे के संपर्क को प्रभावित कर सकती हैं। एक ही उम्र की सभी मछलियों के लिए पारे के खतरों के बारे में जानकारी होने से अलग-अलग उम्र की कई मछलियों के बड़े नमूने एकत्र करने की आवश्यकता को कम करने में मदद मिल सकती है। जिस तरह से वैज्ञानिकों ने पारंपरिक रूप से मूल्यांकन किया है कि कैसे मछलियों को होने वाला खतरा उनके जीवन काल को बदलता है। यह नया तरीका हमें यह समझने में भी मदद कर सकता है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित खतरों को कैसे प्रभावित कर रहा है। जैसे-जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, नदियां, झीलें, मुहाने और महासागर इनमें कुछ घुली हुई ऑक्सीजन को खो रहे हैं। यह प्रक्रिया, जिसे डीऑक्सीजनेशन के रूप में जाना जाता है, जलीय जीवन के लिए एक बड़ी समस्या है। जब एक तालाब या खाड़ी में ऑक्सीजन की मात्रा दो मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे गिरती है, तो सामान्य स्तर पांच से आठ मिलीग्राम प्रति लीटर की तुलना में, उस जल निकाय को हाइपोक्सिक कहा जाता है।

नासा ने मंगल ग्रह पर 'विंटर वंडरलैंड' की खोज की



न्यूयार्क। घन के आकार की बर्फ, बर्फीले परिदृश्य और पाला लाल ग्रह के सबसे ठंडे मौसम का हिस्सा हैं। जब मंगल ग्रह पर सर्दियां आती हैं, तो सतह वास्तव में एक अलौकिक छटा में बदल जाती है। यहां शून्य तापमान के साथ हिमपात, बर्फ और ठंड का प्रभाव दिखता है। इनमें से कुछ सबसे ठंडे ग्रह के ध्रुवों पर पाए जाते हैं, जहां तापमान -123 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है।

मंगल के किसी भी क्षेत्र में कुछ फीट से अधिक बर्फ नहीं गिरती है, जिनमें से अधिकांश अत्यधिक समतल क्षेत्र होते हैं। लाल ग्रह की अण्डाकार कक्षा का मतलब है कि यहां सर्दियों के आने में कई

महीने लगते हैं, एक मंगल वर्ष लगभग दो पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है। फिर भी, ग्रह में अनोखी शीतकालीन घटनाएं होती हैं। यह नासा के रोबोटिक मंगल खोजकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करने को सक्षम बनाती है। यहां कुछ चीजें हैं जो उन्होंने खोजी हैं। मंगल की बर्फ दो तरह की होती है, पहली पानी की बर्फ और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, या सूखी बर्फ। क्योंकि मंगल ग्रह की हवा इतनी पतली है और तापमान इतना ठंडा है, पानी-बर्फ, बर्फ जमीन को छूने से पहले ही वाष्प बन जाती है। सूखी बर्फ या ड्राई-आइस स्नो वास्तव में जमीन तक पहुंचती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में मंगल पर

शोध करने वाले वैज्ञानिक सिल्वेन पिकक्स ने कहा, बर्फ इतनी गिरती है कि आप इसे पार नहीं कर सकते हैं। यदि आप स्कीइंग करना चाहते हैं तो, हालांकि, आपको एक गड्डा या चट्टान में जाना होगा, जहां एक ढलान वाली सतह पर बर्फ का बन सकती है।

कैसे पता चलता है कि यह बर्फ है- बर्फबारी मंगल के केवल सबसे ठंडे चरम हिस्सों पर होती है, जो ध्रुवों पर, बादलों की आड़ में तथा रात में होती है। अंतरिक्ष यान की परिक्रमा करने वाले कैमरे उन बादलों के माध्यम से उसे नहीं देख सकते हैं और सतह पर अत्यधिक ठंड के कारण मिशन के लिए यह संभव नहीं हैं। परिणामस्वरूप, गिरती हुई बर्फ की कोई भी तस्वीर कभी नहीं ली गई

है। लेकिन वैज्ञानिकों को पता है कि ऐसा होता है, कुछ विशेष विज्ञान उपकरणों से ऐसा किया जा सकता है। नासा का मार्स रिक्वैजिनेंस ऑर्बिटर अपने मार्स क्लाइमेट साउंडर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके क्लाइमेट कवर के माध्यम से देखा जा सकता है, जो तरंग दैर्ध्य में प्रकाश का पता लगाता है जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उस क्षमता ने वैज्ञानिकों को जमीन पर गिरने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ का पता लगाने में मदद की है। 2008 में, नासा ने फीनिक्स लैंडर को मंगल के उत्तरी ध्रुव के लगभग 1,600 किलोमीटर के भीतर भेजा, जहां इसने सतह पर पानी-बर्फ गिरने का पता लगाने के लिए एक लेजर उपकरण का इस्तेमाल किया। जमने पर पानी के अणु आपस में कैसे जुड़ते हैं, इस वजह से पृथ्वी पर बर्फ के टुकड़े की छह भुजाएं होती हैं। एक ही सिद्धांत सभी क्रिस्टल पर लागू होता है, जिस तरह से परमाणु खुद को व्यवस्थित करते हैं वह क्रिस्टल के आकार को निर्धारित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में, सूखी बर्फ में अणु जमने पर हमेशा चार तरीके से बंधते हैं। पिक्यूक्स ने कहा कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ में चार की समरूपता होती है, हम जानते हैं कि सूखी बर्फ के टुकड़े घन के

आकार के होंगे। मार्स क्लाइमेट साउंडर के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये बर्फ के टुकड़े मानव बाल की चौड़ाई से छोटे होंगे। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मंगल पर पाले का निर्माण कर सकते हैं और दोनों प्रकार के पाले पूरे ग्रह पर बर्फ की तुलना में कहीं अधिक व्यापक रूप से दिखाई देते हैं। वाइकिंग लैंडर्स ने 1970 के दशक में मंगल ग्रह का अध्ययन करते समय पानी के पाले को देखा गया था, जबकि नासा के ओडिसी ऑर्बिटर ने सुबह के सूरज में पाले के गठन और वाष्प को देखा।

सर्दी का अद्भुत अंत- शायद सबसे शानदार खोज सर्दियों के अंत में आती है, जब सभी तरह की निर्मित बर्फ का पिघलना शुरू होता है। यह बर्फ विचित्र और सुंदर आकार लेती है जिसने वैज्ञानिकों को मकड़ियों, डेलमेटियन धब्बे, तले हुए अंडे और स्विस पनीर की याद दिला दी है। यह पिघलना भी गीजर के फटने की वजह से बनता है, पारभासी बर्फ सूर्य के प्रकाश को इसके नीचे की गैस को गर्म करने की अनुमति देती है और वह गैस अंततः फट जाती है, सतह पर धूल को भेजती है। वैज्ञानिकों ने वास्तव में इन कणों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है ताकि यह पता चल सके कि मंगल ग्रह की हवाएं किस तरफ चल रही हैं।

पूरी तरह अंतरसंबद्ध है हमारी पारिस्थितिकी

मुंबई। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन (कॉप15) मॉन्ट्रियल में गत 19 दिसंबर को संपन्न हुआ। इस आयोजन में वैश्विक जैव विविधता प्रारूप को अपनाया गया जो यह लक्ष्य तय करता है कि 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत क्षेत्रीय, आंतरिक जल और वैश्विक समुद्रों का प्रबंधन संरक्षित क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन लक्ष्यों को राष्ट्रीय लक्ष्यों में कैसे बदला जाएगा या फिर राष्ट्रीय सीमाओं और दायरे के बाहर आने वाले समुद्रों का प्रबंधन कैसे होगा रासायनिक पोषकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर एक अहम लक्ष्य है जो भारत जैसे देशों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।

रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से होने वाले उत्सर्जन को 2030 तक आधा करने तथा जहरीले कीटनाशकों के इस्तेमाल को एक तिहाई करने का लक्ष्य है। भारतीय पर्यावरण मंत्री पहले ही इस प्रावधान को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। एक और लक्ष्य है जो काफी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हो सकता है और वह है 2030 तक प्लास्टिक कचरे को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य। इसके लिए धनराशि जुटाना हमेशा की तरह एक समस्या है। खासतौर पर ऐसे समय में जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरी मुश्किलों से दो-चार है। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सभी संभव स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे ताकि सालाना कम से कम 200 अरब डॉलर की राशि जुटाई जा सके। इसमें नए, अतिरिक्त और प्रभावी वित्तीय संसाधन शामिल होंगे और विकासशील देशों को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता से सालाना 10 अरब डॉलर का इजाफा किया जा सकता है। मैं इसकी व्याख्या विकासशील देशों को सालाना 10 अरब डॉलर की राशि की आश्चर्य के रूप में कर रहा हूँ जो काफी कम धनराशि होगी। एक उल्लेख यह भी है कि सालाना 500 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि उन सब्सिडी को खत्म करके भी जुटाई जाएगी जो जैव विविधता के लिए नुकसानदेह हैं लेकिन यह सभी देशों पर लागू होगी। यह स्पष्ट है कि इस प्रारूप में तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी संसाधन सभी पक्षों को जुटाने होंगे और वह भी बिना साझा लेकिन बंटी हुई जिम्मेदारी तथा संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत लागू किए हुए। इस प्रारूप का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि कम से कम इसके माध्यम से सभी पक्षों ने एक इरादा जताया है लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इसके लिए जरूरी पैमाने पर संसाधन जुटाए जा सकेंगे। बैठक के एजेंडे में एक अहम मुद्दा जेनेटिक संसाधनों और जेनेटिक संसाधनों की डिजिटल सीक्वेंस सूचना तथा जेनेटिक संसाधनों के वाणिज्यिक लाभ से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से संबंधित है। उदाहरण के लिए औषधीय उत्पादों के विकास में इनका इस्तेमाल। प्रारूप के लक्ष्यों में से एक है यह सुनिश्चित करना कि ऐसी उपयोगिता से हासिल होने वाले लाभ साझा और समतापूर्ण ढंग से बांटे जाएं और इस दौरान स्वदेशी लोग और समुदाय भी इसमें शामिल हों। एक सहमति इस बात पर बनी कि ऐसी व्यवस्था बने जिसके माध्यम से जेनेटिक संसाधनों और उनके उपयोगकर्ताओं से संबंधित डिजिटल सीक्वेंसिंग सूचना (जीएसआई) के जरिये हासिल होने वाले लाभों को समतापूर्ण ढंग से साझा भी किया जा सकेगा। इसके लिए एक बहुपक्षीय फंड की स्थापना की जाएगी। इस पहल को तुर्की में 2024 में आयोजित अगली कॉप में अंतिम रूप दिया जाएगा।

भारत में इन 73 प्रजातियों पर गंभीर संकट, अब पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा



नई दिल्ली। भारत में 73 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्यसभा को सूचित किया, जो 2011 में 47 थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रिपोर्ट के अनुसार, 73 प्रजातियों में स्तनधारियों की 9 प्रजातियां, 18 पक्षी, 26 सरीसृप और 20 उभयचर शामिल हैं।

केंद्र अलग-अलग रूप से संकटग्रस्त के रूप में की परियोजनाओं के माध्यम से इन

प्रजातियों की निगरानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व स्तर पर स्वास्थ्य और जैव विविधता की स्थिति की निगरानी करता है। संघ तब एक प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित करता है, जब उस प्रजाति के विलुप्त होने का ज्यादा खतरा माना जाता है। सितंबर 2011 में लोकसभा में मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, मछलियों और उभयचरों की श्रेणी में 47 प्रजातियों की पहचान गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में की गई थी। राज्य सभा में कांग्रेस के

सांसद मुकुल वासनिक ने पर्यावरण राज्य मंत्री, अश्विनी कुमार चौबे से इस विषय पर जवाब मांगा था। चौबे ने कहा कि सरकार अब उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल करने पर विचार कर रही है। मुकुल वासनिक ने पूछा कि क्या सरकार के पास गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए कोई योजना है। इस पर चौबे ने कहा कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त मानी जाने वाली स्तनधारियों की 9 प्रजातियों में से 8 स्थानिक हैं, जिसका मतलब है कि उनकी उपस्थिति भारत के अंदर एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित है।

कौन सी प्रजातियां इसमें शामिल- इनमें कश्मीर स्टैग/हंगुल, मालाबार लार्ज-स्पॉटेड सिवेट, अंडमान श्रू, जेनकिन श्रू, निकोबार श्रू, नामधापा फ्लाइंग स्क्रिबल, लार्ज रॉक रैट और लीफलेटेड लीफनोज्ड बैट शामिल हैं। 18 गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों में बेयर पोचर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोशिएबल

लैपविंग, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल वल्चर जैसे पक्षी हैं। 26 सरीसृप प्रजातियों में से, पांच भारत के लिए स्थानिक हैं जिनमें पिट वाइपर द्वीप भी शामिल है, जिसका आवास कार निकोबार द्वीप में एक ही स्थान तक सीमित है। उभयचरों में, कई प्रजातियां पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास तक सीमित हैं।

मंत्रालय का प्रस्ताव- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि तस्करी को रोकने के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के विभिन्न परिशिष्टों में शामिल किया जाना चाहिए। पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन (COP15) में अपनाए गए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के मद्देनजर चौबे द्वारा जारी की गई जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। समझौते के तहत, 196 सदस्य

देशों ने 2030 तक प्रकृति के लिए दुनिया के 30% हिस्से की रक्षा करने, पर्यावरणीय रूप से हानिकारक सब्सिडी को कम से कम 500 बिलियन प्रति वर्ष कम करने, और कम से कम 30% (क्षेत्र द्वारा) बिगड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने पर सहमति जताई है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत की अधिकांश जैव विविधता भारत के संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। भले ही संरक्षण के तहत 30% कवरेज विश्व स्तर पर लागू होता है न कि अलग-अलग देशों पर, भारत में कुछ बायोम के लिए जहां पूर्ण क्षेत्र सीमित है, हमें संभवतः लगभग 100% जो बचा है उसका संरक्षण करना होगा। इसी तरह, हमारे अत्यधिक लुप्तप्राय मीठे पानी के जलीय जीवों और नदी के पारिस्थितिक तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संरक्षण के लिए, हमें अपनी 30% से अधिक नदियों पर वैकल्पिक भूमि-उपयोग और बांधों और बैराज के प्रबंधन के माध्यम से पारिस्थितिक प्रवाह और तलछट व्यवस्था को बहाल करना पड़ सकता है।

उन्नति की पाठशाला' में बच्चों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

इंदौर। सफाई के मामले में इंदौर ने देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त कर ली है। इस ख्याति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भविष्य की पीढ़ी को अभी से ही सफाई और पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूसी किंडीज स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। जहां बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस के जरिए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया।

इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक ना यूज करने और समुद्र, नदी व अन्य जल स्रोतों में कचरा ना फेंकने के बारे में संदेश दिया। बच्चों ने पेड़ को काटने के से इकोसिस्टम को होने वाले नुकसान के बारे में अपने एक्ट के जरिए जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने फूड चैन और जानवरों के प्रति दया भाव रखने की थीम पर कार्यक्रम पेश किए। साथ ही बच्चों द्वारा सनातन धर्म की रक्षा को लेकर भी कार्यक्रम पेश किए गए। प्रिंसिपल मीता बाफना ने बताया कि वार्षिक उत्सव से पहले 1 हफ्ते तक विभिन्न सेशन चलाया गए। जिसमें जाने-माने डेंटिस्ट को बुला के बच्चों के दांतों का चेकअप कराया गया। इसी के साथ यूसी किंडीज स्कूल ने अपने सेशन में कई एक्टिविटी के जरिए नन्हें बच्चों को हैंडवॉश, बाथिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जंपिंग, टेबल मैनर्स आदि के बारे में सिखाया।

